ग्यासुद्दीन खान उर्फ एमडी ग्यासुद्दीन खान

बनाम

बिहार राज्य

7 नवम्बर 2003

(एस. राजेन्द्र बाबू एवं पी. वेंकटरामा रेड्डी, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860-धारा 302-हत्या-मौत की सजा-औचित्य-अभियुक्त की मानसिक स्थिति-सजा निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक-आरोपी पुलिस कर्मियों ने तीन साथी पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी-हत्या इसलिए की गई क्योंकि मृतकों में से एक ने उसे डांटा था और रजिस्टर में उसके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज की थीं-अन्य दो पुलिस कर्मियों को मारने का कोई मकसद नहीं-उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया-दंड-मौत की सजा।

अपीलकर्ता पुलिस बल में कांस्टेबल था। वह अपने वरिष्ठ आर की कार्रवाई से दुखी था, जिसने उसे लापरवाही और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी के लिए कई मौकों पर फटकार लगाई थी। आर ने गाड्र्स रजिस्टर में उनके खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ भी की थीं। जब आर ध्यान कर रहा था, अपीलकर्ता ने अपनी स्टेन-गन ली और उसे गोली मार दी। इसके

बाद उसने एक अन्य सहकर्मी सी की हत्या कर दी, जिसने उसे चुनौती दी थी। यह सब देख रहा एक अन्य पुलिस कर्मी बी अपनी सुरक्षा के लिए भागा। अपीलार्थी ने उसका पीछा कर पास के खेत में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। स्टेन-गन की मैगजीन ख़त्म होने के बाद, अपीलकर्ता ने बी की स्टेन-गन ले ली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद, जब पुलिस कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया तो उसने बंदूक फेंक दी और भागने की कोशिश की।

अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता ने खुद को निर्दोष बताया और दलील दी कि पुलिस स्टेशन पर चरमपंथियों द्वारा हमला किया गया था जिन्होंने मृत व्यक्तियों की हत्या कर दी थी।

ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को धारा 302 आई.पी.सी. और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी गई और मृत्यु संदर्भ को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसलिए अपील करना जरूरी ।

सजा के प्रश्न पर अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. अपीलकर्ता को धारा 302 आई.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया गया। कायम रखा गया है महत्वपूर्ण समय पर शिविर में मौजूद सभी चश्मदीदों का बयान काफी सुसंगत और विश्वसनीय है। उन्होंने कुछ मिनटों तक चली इस घटना का विवरण दिया है जिसमें तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। उन्होंने मकसद, यानी फटकार और रजिस्टर में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में भी बात की है। साथी पुलिसकर्मियों के पास उस आरोपी को फंसाने के लिए कोई कहानी गढ़ने का कोई कारण नहीं था, जिसके खिलाफ उनमें से किसी की भी कोई दुश्मनी नहीं थी। (376-ई; 373-ई, एफ)

1.2. आरोपियों के मुताबिक अगर इस घटना के लिए कुछ हथियारबंद बाहरी लोग जिम्मेदार होते तो साथी पुलिसकर्मी उस घटना को दबाने और आरोपियों को मिलकर साजिश रचने की हद तक नहीं जाते. बचाव पक्ष के गवाह कभी भी पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने के लिए आगे नहीं आए। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी क्यों रोकनी चाहिए। (376-बी)

शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि पर

2. शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है। ई आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत

अपराध के संबंध में ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस्तेमाल किया गया हथियार, अर्थात् स्टेन-गन, शस्त्र अधिनियम की धारा 2 (1) (आई) के अर्थ के भीतर 'निषिद्ध हथियार' के विवरण का उत्तर देता है, हालांकि, सभी संभावनाओं में, यह हो सकता है। अपीलकर्ता को धारा 27(3) के तहत दोषी ठहराना उचित नहीं है जिसमें मौत की कठोर सजा का प्रावधान है। (380-एफ, जी; 381-ए)

मौत की सज़ा पर

3.1. मौजूदा मामले में मौत की सज़ा उचित सज़ा नहीं है। (380-डी)

3.2. मृत्युदंड केवल अत्यंत दुर्लभ और हत्या के अत्यंत गंभीर मामलों में ही दिया जाना चाहिए। मारे गए व्यक्तियों की संख्या, हालांकि एक कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, अपराधी को मौत की सजा देने के लिए एकमात्र विचार नहीं होना चाहिए। विभिन्न कारकों जैसे कि जो आरोपी की मनःस्थिति, प्रेरणा, दृष्टिकोण और प्रवृत्ति के बारे में जानकारी देते हैं, का एक नाजुक संतुलन बनाना होगा और साथ ही, व्यापक सामाजिक हितों को ध्यान में रखना होगा। सिद्धांत यह है कि के मामले में हत्या, आजीवन कारावास सामान्य नियम है और मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। दुर्लभतम मामलों में न्यायाधीश का निर्णय सौंपा जाना निश्चित रूप से सर्वोच्च होना चाहिए। (1376-जी-एच; 377-ए)

3.3. यद्यपि कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, प्रथम दृष्टया, एक खतरनाक अपराधी जो अपने स्वार्थी लाभ प्राप्त करने या अपनी शारीरिक वासना को पूरा करने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए बेहद क्रूर और भयानक तरीके से हत्या की होड़ में शामिल हुआ है और शांति को समाज के लिए खतरा माना जाना चाहिए और उसे मौत की कठोर सजा दी जानी चाहिए। हालाँकि, ऐसे मामलों में भी, परिस्थितियों को कम करना अनुचित नहीं है। (1377-ए, बी)

3.4. जबकि मौत की सज़ा दुर्लभ से भी दुर्लभ मामलों में दी जानी चाहिए, जब तक कि कानून इसके लिए प्रावधान करता है और ऐसा कानून न्यायिक जांच में खरा उतरा है, अदालत इसे एक मृत पत्र नहीं बना सकती है और मौत की सज़ा देने से इनकार नहीं कर सकती है जहां इससे कम कुछ भी नहीं है उचित एवं पर्याप्त होगा। मृत्युदंड के पीछे का औचित्य अत्यधिक क्रूरता और आतंकवाद के अपराधों के संबंध में समाज की सामूहिक चेतना का सम्मान करना और समाज को सुरक्षा प्रदान करना है। निःसंदेह निरोध का तत्व इसमें अंतर्निहित है। मौत की सज़ा तीन उद्देश्यों को पूरा करती है (1) दंडात्मक (2) निवारक और (3) सुरक्षात्मक। (377-सी-डी)

एडिगा अनाम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1974) 4 एससीसी 443; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684; शेख इशाक

बनाम बिहार राज्य, (1995) 3 एससीसी 392 और अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य, (1989) 3 एससीसी 5 का उल्लेख किया गया है।

3.5. अपराध की प्रकृति, अपराधी की परिस्थितियाँ और समुदाय पर अपराध का प्रभाव मोटे तौर पर ऐसे विचार हैं जिन्हें अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए और मृत्युदंड और आजीवन कारावास के बीच चयन करना चाहिए। साथ ही, जिन परिस्थितियों में मौत की सजा दी जा सकती है, उन्हें कबूतरखाने में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक मामले में प्रस्तुत तथ्यों पर समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। (377-ई, एफआई)

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684 और माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एससीसी 470 का उल्लेख किया गया है।

3.6. अभियुक्त की मानसिक स्थिति या मानसिक स्थिति उन कारकों में से एक है जिसे विभिन्न मामलों में वैध रूप से ध्यान में रखा गया है और सजा के प्रश्न पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें अदालत परेशान के संबंध में विचार कर रही है। अपराध के समय अभियुक्त की असंतुलित मानसिक स्थिति के कारण मृत्युदंड न देना उचित समझा गया। (379-ई, एफ)

शामहुल कंवर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1995) 4 एससीसी 430; लहना बनाम हरियाणा राज्य, (2002) 3 एससीसी 76; ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (1999), 3 एससीसी 19 और फ्रांसिस बनाम केरल राज्य, (1975) 3 एससीसी 825, का उल्लेख किया गया है।

3.7. बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य या लाभ के आर की हत्या करने का यह कृत्य अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति को उजागर करता है। अपीलकर्ता का ऐसा असामान्य और हताश व्यवहार उसके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को उजागर करता है। अपीलकर्ता की जो छवि उभरती है वह एक अति-संवेदनशील, अति-भावनात्मक, आत्म-केंद्रित और गर्म दिमाग वाले व्यक्ति की है जिसमें संयम और दूरदर्शिता का सर्वथा अभाव है। ऐसा लगता है कि उनमें लगभग एक विक्षिप्त प्रवृत्ति थी, जिसने उन्हें अपने और अपने परिवार पर पड़ने वाले स्पष्ट परिणामों के बारे में सोचे बिना अपने वरिष्ठ अधिकारी की जान लेने के चरम कदम पर मजबूर कर दिया था। अपने अधिकारी के प्रति अपमान, मानसिक तनाव, आक्रोश और प्रतिशोध की भावनाएँ स्पष्ट रूप से उस पर हावी हो गई हैं। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने बेहद परेशान और असंतुलित मन की स्थिति में काम किया। बिना सोचे-समझे और बिना किसी मकसद के दो पुलिसकर्मियों की हत्या से यह भी पता चलता है कि ये कृत्य घबराहट की प्रतिक्रिया और उन्माद की स्थिति में किए गए थे। ऐसा मामला नहीं है जहां यह निश्चित रूप से कहा जा

सके कि जानलेवा हमले संकल्पना में शैतानी और निष्पादन में क्रूर थे। न ही यह कहा जा सकता है कि 'अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थितियों से पता चला कि अपराधी समाज के लिए खतरा हैं या यदि मृत्युदंड नहीं दिया गया तो 'समुदाय की सामूहिक चेतना को झटका लगेगा' तात्कालिक मामला. सबसे बढ़कर, मौत की सज़ा उसे काफी समय से परेशान कर रही है। (379-बी-डी; 380-ए-सी)

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684; अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य, (1989) 3 एससीसी 5 और रणधीर बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2000) 3 एससीसी 161, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 190/2002

पटना उच्च न्यायालय सी.आर.आई.ए. (डीबी) संख्या 165/2000 में के निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.9.2001 से।

अपीलार्थी की ओर से अमरेन्द्र शरण और कृष्णानंद पांडे,

ग्यासुद्दीन खान बिहार राज्य (रेड्डी, जे) 371

प्रत्यर्थी की ओर से एच.एल. अग्रवाल और कुमार राजेश सिंह।

न्यायालय का निर्णय पी. वेंकटराम रेड्डी, जे. द्वारा सुनाया गया।

9 अप्रैल, 1996 की सुबह, बिहार के एक गाँव के पास स्थित एक पुलिस शिविर के परिसर में, एक आतंकवादी ऑपरेशन के समान एक भयावह घटना घटी। आरोपी पुलिसकर्मी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस पिकेट में तैनात था, जिसने गोलीबारी करके अपने तीन साथियों की तुरंत हत्या कर दहशत पैदा कर दी। मुक़दमे के बाद उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है. वह अब दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है-

अपीलकर्ता बिहार के भोजपुर जिले के चकरदाह गांव के पास नरही पुलिस शिविर में तैनात पुलिसकर्मियों में से एक था। वह एक कांस्टेबल थे जिन्हें ब्लैक कमांडो के रूप में भी प्रशिक्षित किया गया था। वह हवलदार राम पांडे द्वारा एक बार छत पर सोते समय राइफल को भूतल पर छोड़ने और दूसरी बार ड्यूटी के दौरान रेडियो सुनने और गार्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि देने के लिए फटकार लगाने की कार्रवाई से व्यथित था। इन खामियों के लिए रजिस्टर करें। 9 अप्रैल, 1996 को सुबह लगभग 8 बजे जब श्री राम पांडे एक खाट पर बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, अपीलकर्ता ने अचानक खाट पर रखी राम पांडे की स्टेन-गन उठा ली और उन्हें गोली मार दी। श्री चन्द्रशेखर सिंह, एस.आई., जो उस समय वाटर पंप के पास स्नान कर रहे थे, ने उनसे पूछताछ की। उसे भी नहीं बख्शा गया. आरोपी ने अपनी

स्टेनगन से गोलियां चलाईं और उसी समय हवलदार भागीरथ सिंह सहित उसके अन्य साथी सुरक्षा के लिए भाग गए। अपीलकर्ता ने भाग रहे भागीरथ सिंह पर गोलियां चलाईं और मिट्टी की दीवार से अलग हुए पास के प्याज के खेत तक उसका पीछा किया। उस पर गोली चलाने के बाद आरोपी जिस स्टेनगन को संभाल रहा था, उसकी मैगजीन खत्म हो गई. उन्होंने भागीरथ सिंह की स्टेनगन निकाल ली और 'फट' फायरिंग कर दी. गोली लगने से तीनों लोगों की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद, जब अपीलकर्ता ने दोनों स्टेन-गन फेंक दीं और अपनी एसएलआर के साथ भागना चाहा, तो पुलिस कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया।

सूचना पर कंपनी कमांडर (पीडब्लू7) और उदवंतनगर पुलिस स्टेशन (सीडब्ल्यू1) के एस.आई. पुलिस पिकेट पहुंचे और मौके पर पीडब्लू 3 का बयान दर्ज किया और उसे एफ.आई.आर. माना गया। उन्होंने जांच शुरू की, अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए, जांच रिपोर्ट तैयार की और तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। उसने एक के पास से पांच अदद कारतूस के खाली खोल बरामद किये।

जिस स्थान पर राम पांडे को गोली मारी गई थी उसके करीब एक स्थान और पुलिस पिकेट से सटी सड़क पर 18 की संख्या में कारतूस के खाली खोल, उसने रक्तरंजित मिट्टी भी जब्त कर ली। बैलिस्टिक विशेषज्ञ, जिनके पास मृतक राम पांडे और भागीरथ सिंह की स्टेनगन जांच के लिए

भेजी गई थीं, ने राय दी कि वे काम करने की स्थिति में थे और इस आशय की एक रिपोर्ट आई ओ को भेजी। शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पढ़ी जाने वाली आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए।

अपीलकर्ता ने बचाव में कहा कि 9 अप्रैल, 1996 को कुछ चरमपंथी पुलिस पिकेट में घुस आए और पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों की मृत्यु हो गई। इस याचिका के समर्थन में, अभियुक्त ने बचाव पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की बचाव पक्ष का संस्करण को ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया था। दोनों अदालतों ने उन चश्मदीद गवाहों के बयान पर भरोसा किया जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन धरने पर मौजूद थे और उन्होंने अपराध का निष्कर्ष निकाला। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए संदर्भ को पटना उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अभियुक्त द्वारा दायर अपील डी खारिज कर दी गई। इस अदालत ने अपील करने की विशेष अनुमति दी और मौत की सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

आगे बढ़ने से पहले, हम संक्षेप में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 5 से 5/2) और सदर अस्पताल से जुड़े चिकित्सा अधिकारी पी.डब्लू.6 के साक्ष्य

का उल्लेख करेंगे, जिन्होंने घटना के दिन ही पोस्टमॉर्टम किया था। उन्होंने राम पांडे के शव पर आठ चोटें देखीं जो कटे घावों की प्रकृति की थीं। उनके अनुसार, सभी चोटें बन्दूक से लगी थीं। उन्हें सीने की दीवार में पिछले हिस्से में एक गोली लगी मिली। उन्होंने गर्दन के बाईं ओर, पीठ के ऊपरी हिस्से और छाती पर प्रवेश के घावों और बाहर निकलने के घावों का वर्णन किया। खोपड़ी के विच्छेदन एफ पर, उन्होंने देखा कि मस्तिष्क और मेनिन्जेस क्षतिग्रस्त हो गए थे और खोपड़ी और मज्जा के बाईं ओर घाव हो गए थे। दायां फेफड़ा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पी.डब्ल्यू 6 की राय है कि मौत बन्दूक की गोलियों से मस्तिष्क, फेफड़े और छाती को हुए नुकसान के कारण हुई।

चन्द्रशेखर सिंह के मृत शरीर पर, पी.डब्ल्यू. 6 को आग्नेयास्त्र के कारण जो-नौ चोटें मिलीं। उनमें से सबसे गंभीर था सामने पार्श्विका खोपड़ी के दाहिनी ओर एक फटा हुआ घाव, जो प्रवेश का घाव था और पश्चकपाल खोपड़ी के बाईं ओर एक निकास का घाव था जिसके माध्यम से मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकल रहा था। एक और गंभीर घाव छाती के दाहिनी ओर एक गोल घाव था जो प्रवेश का

ग्यासुद्दीन खान बिहार राज्य (रेड्डी जे) 373 घाव था। उन्होंने कहा कि मृत्यु महत्वपूर्ण अंगों मस्तिष्क, गर्दन, रीढ़ की हड्डी और दायां फेफड़ो में क्षति के कारण हुई।

पी.डब्ल्यू. 6 को भागीरथ सिंह के शव पर पाँच चोटें मिलीं जो गोल छेदने वाले घावों और गोल घाव वाले घावों की प्रकृति में थीं। उन्होंने प्रवेश और निकास के विभिन्न घावों का विवरण दिया। प्रवेश के घाव दाहिने कंधे पर और दाहिने कान के पीछे आदि थे। विच्छेदन करने पर, उन्होंने मस्तिष्क पदार्थ और मेनिन्जेस को बन्दूक के मार्ग के साथ फटा हुआ और घावों से घायल पाया। चेस्ट दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त पाया गया। हृदय छेदा हुआ और क्षतिग्रस्त पाया गया। डॉक्टर की राय थी कि बन्दूक से मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को हुई क्षति के कारण उनकी मृत्यु हुई। पीडब्लू 6 ने स्पष्ट किया कि प्रवेश घावों की प्रकृति से, यह कहा जा सकता है कि गोलीबारी करीब से हुई थी।

इस प्रकार चिकित्सा साक्ष्यों से यह साबित हो गया है कि आग्नेयास्त्र से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर लगी गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हुई है। घटना के चार प्रत्यक्षदर्शी कांस्टेबल-पीडब्लू 1 से 3 और 5 हैं। पीडब्लू 7 पुलिस पिकेट का कंपनी कमांडर था, जो गोलीबारी की आवाज सुनकर और पीडब्लू 1 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने पर, सब की कंपनी में तुरंत घटना स्थल पर आया। उदवंतनगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी थाना प्रभारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच की, कोर्ट गवाह नंबर 1 के रूप में जांच की गई।

हमने पाया, जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया, कि महत्वपूर्ण समय पर शिविर में मौजूद सभी चश्मदीदों का बयान काफी सुसंगत और विश्वसनीय है। उन्होंने कुछ मिनट तक चली इस घटना का विवरण दिया है, जिसमें तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। उन्होंने मकसद, यानी फटकार और रजिस्टर में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में भी बात की है। साथी पुलिसकर्मियों के पास उस आरोपी को फंसाने के लिए कोई कहानी गढ़ने का कोई कारण नहीं था, जिसके खिलाफ उनमें से किसी की भी कोई दुश्मनी नहीं थी। आरोपियों के मुताबिक अगर इस घटना के लिए कुछ हथियारबंद बाहरी लोग जिम्मेदार होते तो साथी पुलिसकर्मी उस घटना को दबाने और आरोपियों को मिलकर साजिश रचने की हद तक नहीं जाते. जिस स्थिति से आरोपी ने पीड़ितों पर अपने हथियार का निशाना बनाया, उसके संबंध में कुछ विसंगतियां बताई गईं। तब यह बताया गया कि कोई और घायल नहीं हुआ, हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने अंधाधुंध गोलीबारी का सहारा लिया। आगे यह टिप्पणी की गई कि पी.डब्ल्यू. 3 जो बंदूक के साथ संतरी ड्यूटी पर था, उसे अपीलकर्ता पर गोली चलानी चाहिए थी यदि वह असली अपराधी था। फिर, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा गांव के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई, जबकि घटना गांव के आसपास ही हुई इसी तरह के तर्कों को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हम यह नहीं सोचते कि किसी भी

उचित मानक के अनुसार, ये कारक भारी अभियोजन साक्ष्य पर सेंध लगाएंगे।

इसी तरह, अभियोजन पक्ष के संस्करण पर हमला करने के लिए जांच अधिकारी की कुछ पी.डब्ल्यू. 2 को भी पेश किया गया है। उदाहरण के लिए, यह बताया गया कि इस तथ्य को जानने के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई थी कि बरामद किए गए खाली कारतूस विशेष स्टेन-गन से फायर किए गए होंगे और राम पांडे और भागीरथ सिंह के शरीर में पाए गए छर्रे का पता लगाया जा सकता है। विशेष बी स्टेन-गन। इसके अलावा, खून से सनी मिट्टी और आरोपी की शर्ट को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा जाना चाहिए था और रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी। जांच में ये खामियां, चाहे जो भी कारण हों, किसी भी भौतिक सीमा तक, उन सबसे स्वाभाविक प्रत्यक्षदर्शियों की सत्यता को प्रभावित नहीं करती हैं जिन्होंने एक सुसंगत संस्करण दिया है और जो जल्द से जल्द अवसर पर इस संस्करण के साथ आगे आए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के बीच, ऐसा प्रतीत होता है कि पीडब्लू 2 पहले पीड़ित, राम पांडे पर हमले को देखने की स्थिति में नहीं हो सकता था क्योंकि वह घटनास्थल से थोड़ी दूर मेस में खाना बना रहा था। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की आवाज सुनने के बाद, वह और दो अन्य (जिनकी जांच नहीं की गई) दीवार के पीछे छिप गए। इसी तरह पीडब्लू 5, जो एक

कोने पर पेशाब कर रहा था, उसने राम पांडे को आरोपी द्वारा गोली मारते हुए नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कि राम पांडे जहां बैठे थे, वह पेशाब करने की जगह से दिखाई नहीं दे रहा था हालांकि, यह कहा गया कि गार्ड रूम से गोलीबारी की आवाज सुनने के बाद, उन्होंने उस दिशा की ओर देखा और देखा कि आरोपियों ने राम पांडे की हत्या कर दी थी और उसके बाद उन्होंने चन्द्रशेखर सिंह को निशाना बनाया और उन्हें गोली मारने के बाद आरोपियों ने भागीरथ सिंह को निशाना बनाया. हो सकता है कि कुछ गवाह ने राम पांडे को गोली लगते नहीं देखा होगा और उन्हें इसका एहसास हो गया होगा। गोलीबारी के तुरंत बाद. लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से बंदूकधारी आरोपी को आक्रामक और उसके आगे की गोलीबारी की हरकतों को देखा होगा। गोलीबारी बंद होने के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें तीन पीड़ितों के शव मिले। भले ही एफ उस अर्थ में प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह न हों, गोलियों की आवाज सुनने और उसके तुरंत बाद हाथ में बंदूक के साथ आरोपी की हरकतों को नोटिस करने के बारे में उनका सबूत अन्य चश्मदीदों के बयान को मजबूत समर्थन देता है। यह आरोपी और अकेले आरोपी पर भयानक कृत्य की जिम्मेदारी तय करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में भी काम करता है।

यह तर्क दिया गया कि एफ.आई.आर. में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। भागीरथ सिंह पर हमले के बारे में पी.डब्ल्यू. 3 द्वारा दिया गया।

हालाँकि, उन्होंने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता को पकड़ने के तुरंत बाद, उन्होंने शिविर के उत्तर की ओर स्थित मैदान में हवलदार भागीरथ सिंह का शव देखा। हो सकता है, उसने असल में आरोपी को भागीरथ सिंह पर गोली चलाते नहीं देखा होगा क्योंकि हत्यारे की गोलियाँ चन्द्रशेखर सिंह पर गिरने के बाद वह (पीडब्लू3) दीवार के पीछे छिप गया और इसलिए एफ.एल.आर. में इसका उल्लेख करना छोड़ दिया।

फिर भी, अभियोजन पक्ष का मामला प्रभावित नहीं होता है। पी.डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य भागीरथ सिंह की मौत और अपीलकर्ता द्वारा की गई गोलीबारी के बीच अटूट संबंध को उजागर करते हैं। इसके अलावा, अन्य सबूत भी हैं जो अपीलकर्ता द्वारा भागीरथ सिंह पर हमले के अभियोजन मामले का समर्थन करते हैं। हमारे पास पीडब्लू 1 और 4 के साक्ष्य हैं जो घटना से ठीक पहले मृतक भागीरथ सिंह के साथ एक खाट पर बैठे थे। पीडब्ल्य 1 ने कहा कि जब वे सुरक्षा के लिए भाग रहे थे, तो भागीरथ सिंह-जो पीछे था, को गोली लग गई और वह आम के पेड़ के पीछे छिप गया। पीडब्लू 4 ने भी लगभग यही संस्करण दिया। भागीरथ सिंह पर हमले के विवरण को विस्तार से बताते हुए, पी.डब्ल्यू.4 ने कहा कि आरोपी ने प्याज के खेत की मेड़ पर उसे गोली मार दी और वह उसी स्थान पर गिर गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने प्याज के खेत के पूर्व की ओर स्थित दीवार के पीछे शरण ली थी और वह घटना को देखने में सक्षम

थे, हालांकि आरोपी नहीं देख सके। सबसे बढ़कर, सभी गवाहों-पीडब्ल्यू 1 से 5 तक के साक्ष्य हैं कि हत्यारे की बंदूक से गोलीबारी बंद होने और उसे काबू करने के तुरंत बाद उन्हें प्याज के खेत में भागीरथ सिंह का शव मिला। इसलिए सबूत उचित संदेह से परे स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता के अलावा किसी और ने स्टेन-गन से चलाई गई गोलियों से हवलदार भागीरथ सिंह की हत्या नहीं की। इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि भागीरथ सिंह तब तक एक-दो गोली लगने के बाद भी निचली मिट्टी की दीवार को फांदकर प्याज के खेत में पहुंच जाएगा।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भागीरथ सिंह को भागते समय गोली मारी गई थी, लेकिन शरीर के सामने यानी छाती पर एक घाव था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने बताया, इस बात की पूरी संभावना थी कि भागीरथ सिंह का सामना किसी न किसी स्तर पर आरोपियों से होगा। यह उम्मीद करना उचित नहीं है कि डरे हुए प्रत्यक्षदर्शी भागीरथ सिंह को लगी गोलियों का सूक्ष्म और सटीक विवरण दे पाएंगे। तब यह तर्क दिया गया कि भागीरथ सिंह के शव पर पाए गए प्रवेश घाव 1, 3 और 5 पर जले हुए निशान से संकेत मिलता है कि गोलीबारी करीब से की गई थी, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। लेकिन, भागीरथ सिंह का शव पुलिस पिकेट से कुछ दूरी पर

स्थित प्याज के खेत में मिला. विद्वान वकील के अनुसार, इससे संकेत मिलता है कि गोलीबारी नजदीक से नहीं की जा सकती थी। केवल इस तथ्य से कि भागीरथ सिंह बगल के खेत में पहुंचकर गिर पड़े, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें नजदीक से गोली नहीं लगी थी। न्यायालय घबराए हुए प्रत्यक्षदर्शियों से दूरी का स्पष्ट विवरण देने की उम्मीद नहीं कर सकता जिसमें से हर एक पर गोली चलाई गई थी। नजदीक से फायरिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा बचाव पक्ष के गवाहों के बयान पर सही ढंग से अविश्वास किया गया। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये गवाह कभी भी पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने के लिए आगे नहीं आए। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी क्यों रोकनी चाहिए। बचाव पक्ष के गवाह 1 से 5 सर्वव्यापी बयान के साथ आगे आए कि राइफल और बंदूकों से लैस दस से पंद्रह लोग पुलिस पिकेट की ओर से आए और पिकेट को घेरने के बाद गोलीबारी शुरू कर दी। उनमें से कुछ ने कहा कि उन्होंने कैंप सी के अंदर कुछ लोगों को गोली लगने के बाद जमीन पर गिरते हुए देखा और आगे कहा कि उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को भागते हुए देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उन कथित बदमाशों में से किसी की भी वे पहचान नहीं कर सके। ट्रायल कोर्ट ने पैराग्राफ 18 और 19

पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषण और संभावनाओं पर उनके साक्ष्य को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय की चर्चा पैराग्राफ 22 पर है। हम ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि बचाव साक्ष्य भरोसेमंद नहीं हैं।

भारी और निर्विवाद सबूतों के प्रकाश में, यह संदेह की छाया से परे स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ता ने तीन पुलिसकर्मियों, अर्थात् राम पांडे (हवलदार), चन्द्रशेखर सिंह (एस) और भागीरथ सिंह (हवलदार) की हत्या कर दी। राम पांडे की चौकी से बंदूक उठा ली. इसलिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की सजा बरकरार रखी जाती है।

(1974) 4 एससीसी 443 में कृष्णा लायर जे के अनुसार एक बार अपराध स्थापित हो जाता है, दंडात्मक दुविधा शुरू हो जाती है और यह दुविधा तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब अपराध की भयावहता बहुत अधिक हो जाती है, जिसे अपराधी द्वारा पहुंचाए गए हताहतों की संख्या के कोण से देखा जाता है। बचन सिंह के मामले में (1980) 2 एससीसी 684, मौत की सज़ा संवैधानिक वैधता की कसौटी पर खरी उतरी है। यह हमारे दंड-विज्ञान के नियम का हिस्सा बनकर रह गया है। साथ ही, इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि मृत्युदंड केवल हत्या के बहुत ही दुर्लभ और असाधारण गंभीर मामलों में ही दिया जाना चाहिए। ईमानदारी से देखभाल और मानवीय चिंता न्यायालय के दृष्टिकोण को सूचित करना चाहिए. शेख जी इशाक बनाम बिहार राज्य, (1995) 3 एससीसी 392 में

अन्य मामलों के अलावा इस न्यायालय का विचार यह है कि मारे गए व्यक्तियों की संख्या, हालांकि ध्यान में रखा जाने वाला एक कारक है, पर एकमात्र विचार नहीं किया जाना चाहिए। अपराधी को मौत की सजा दो. विभिन्न कारकों का एक नाजुक संतुलन, जैसे कि जो आरोपी की मनःस्थिति, प्रेरणा, दृष्टिकोण और प्रवृत्ति के बारे में जानकारी देते हैं, एक ही समय में बड़े सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए के साथ होना चाहिए।

हत्या के मामले में आजीवन कारावास सामान्य नियम है और दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा दी जानी चाहिए, यह निश्चित रूप से न्यायाधीश के दिमाग में सबसे ऊपर होना चाहिए। यद्यपि कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, प्रथम दृष्टया, एक खतरनाक अपराधी जो अपने स्वार्थी लाभ प्राप्त करने या अपनी शारीरिक वासना को पूरा करने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए बेहद क्रूर और भयानक तरीके से हत्या की होड़ में शामिल हुआ है और शांति को समाज के लिए खतरा माना जाना चाहिए और उसे मौत की कठोर सजा दी जानी चाहिए। हालाँकि, ऐसे मामलों में भी, परिस्थितियों को कम करना अनुचित नहीं है। जबकि मौत की सज़ा दुर्लभतम मामलों में दी जानी चाहिए, जब तक कि कानून इसके लिए प्रावधान करता है और ऐसा कानून न्यायिक जांच का सामना कर चुका है, अदालत इसे एक मृत पत्र नहीं बना सकती

है और मौत की सजा देने से इनकार नहीं कर सकती है जहां इससे कम कुछ भी नहीं है। उचित एवं पर्याप्त होगा. मृत्युदंड के पीछे का औचित्य अत्यधिक क्रूरता और आतंकवाद के अपराधों के संबंध में समाज की सामूहिक चेतना का सम्मान करना और समाज को सुरक्षा प्रदान करना है। निःसंदेह निरोध का तत्व इसमें अंतर्निहित है। जैसा कि अलाउद्दीन मियां के मामले में बताया गया है (1989) 3 एससीसी 5 मौत की सजा तीन उद्देश्य पूरा करती है (1) दंडात्मक (2) निवारक और (3) सुरक्षात्मक।

अपराध की प्रकृति, अपराधी की परिस्थितियाँ और समुदाय पर अपराध का प्रभाव मोटे तौर पर ऐसे विचार हैं जिन्हें अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए और मृत्युदंड और आजीवन कारावास के बीच चयन करना चाहिए। साथ ही, जिन परिस्थितियों में मौत की सजा दी जा सकती है, उन्हें कबूतरखाने में नहीं रखा जा सकता। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684 के मामले में गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों की गणना विस्तृत नहीं है और इसका उद्देश्य न्यायिक विवेक को बाधित करना नहीं है। इस न्यायालय ने सावधानी से कहा कि वे व्यापक संकेतक या दिशानिर्देश हैं और उसने सजा प्रक्रिया के संबंध में कठोर मानक तैयार करने का प्रस्ताव नहीं किया है। प्रगणित कारकों में से प्रत्येक को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक मामले में प्रस्तुत तथ्यों पर समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस संदर्भ में, हम बचन

सिंह के मामले में संविधान पीठ के लिए बोलते हुए सरकारिया जे द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत कर सकते हैं।

''जैसा कि हमने धारा 354(3) और 235(2) और अन्य संबंधित प्रावधानों को पढ़ा है 1973 की संहिता से, हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव करने के लिए सज़ा का या विशेष के अस्तित्व या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए कारण उस संदर्भ में, न्यायालय को दोनों पर उचित ध्यान देना चाहिए अपराध और अपराधी. सापेक्षिक भार कितना दिया जाना चाहिए। उत्तेजित करने वाले और कम करने वाले कारक, विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अक्सर, ये दोनों पहलू इतने आपस में जुड़े हुए होते हैं कि उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग उपचार देना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टाइल ही आदमी है। कई मामलों में, हत्या करने का अत्यंत क्रूर या पाशविक तरीका स्वयं अपराधी के भ्रष्ट चरित्र का एक प्रदर्शित सूचकांक है। इसीलिए, अपराध की परिस्थितियों और अपराधी की परिस्थितियों पर दो अलग-अलग निर्विवाद डिब्बों में विचार करना वांछनीय नहीं है। एक अर्थ में, हत्या करना क्रूर होना है और इसलिए सभी हत्याएँ क्रूर हैं। लेकिन ऐसी क्रूरता की दोषीता की डिग्री अलग-अलग हो सकती है। और यह तभी होता है जब दोषी अत्यधिक भ्रष्टता का अनुपात मान लेता है कि विशेष कारण को वैध रूप से अस्तित्व में कहा जा सकता है। (जोर दिया गया)''

तब इस ओर ध्यान दिलाया गया था

> "विकट परिस्थितियों की कोई विस्तृत गणना संभव नहीं है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि विकट परिस्थितियों की श्रेणी में शामिल करने की गुणवत्ता के लिए, जो धारा 354 (3) में विशेष कारणों का आधार बन सकती है, परिस्थितियों पर पाया गया किसी विशेष मामले के तथ्यों में किसी असामान्य या विशेष डिग्री की वृद्धि का साक्ष्य होना चाहिए।"
>
> (जोर दिया गया)

माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य में, (1983) 3 एससीसी 470, इस न्यायालय के बाद

बचन सिंह के मामले में विज्ञापित दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित कार्य परीक्षण लागू किया गया कि क्या किसी विशेष मामले में मौत की सजा की आवश्यकता है-

(ए) क्या अपराध के बारे में वाक्य कुछ असामान्य है जो प्रस्तुत करता है आजीवन कारावास की सज़ा अपर्याप्त है और मृत्युदंड की मांग की गई है?

(बी) क्या अपराध की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

अब, हम अपना ध्यान सजा के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाले प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर केन्द्रित करेंगे। अपीलकर्ता व्यथित था

हवलदार राम पांडे की गलती ए या अनुशासनहीन व्यवहार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने की कार्रवाई से। फिर भी, अपने और अपने परिवार के भविष्य की परवाह करने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति हवलदार को उसके सभी सहयोगियों की उपस्थिति में खुलेआम हत्या करने जैसा चरम कदम उठाकर अपने साथ हुए कथित गलत का बदला लेने का जोखिम नहीं उठाएगा। राम पांडे की हत्या का यह कृत्य, जिसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, कोई लाभ या लाभ प्राप्त करना, अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति को प्रकट करता है। अपीलकर्ता का ऐसा असामान्य और हताश व्यवहार उसके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को उजागर करता है। हमें अपीलकर्ता की छवि एक अति-संवेदनशील, अति-भावनात्मक, आत्म-केन्द्रित और क्रोधी व्यक्ति के रूप में मिलती है जिसमें संयम और दूरदर्शिता का सर्वथा अभाव है। वास्तव में, पी.डब्ल्यू. 7 के साक्ष्य अपीलकर्ता की इन विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, जब वह अभियुक्त को मनभ्रद और मनशोख के रूप में वर्णित करता है। हमें ऐसा लगता है कि उनमें लगभग एक विक्षिप्त प्रवृत्ति

थी, जिसने उन्हें अपने और अपने परिवार पर पड़ने वाले स्पष्ट परिणामों के बारे में सोचे बिना अपने वरिष्ठ अधिकारी की जान लेने के चरम कदम पर मजबूर कर दिया था। अपने अधिकारी के प्रति अपमान, मानसिक तनाव, आक्रोश और प्रतिशोध की भावनाए स्पष्ट रूप से उस पर हावी हो गई हैं। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने बेहद परेशान और असंतुलित मन की स्थिति में काम किया। वास्तव में, गवाहों में से एक, अर्थात् पीडब्लू 4 ने इस तथ्य से बात की कि मृतक राम पांडे द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के बाद आरोपी बहुत परेशान था।

अभियुक्त की मानसिक स्थिति या मानसिक स्थिति उन कारकों में से एक है जिसे विभिन्न मामलों में वैध रूप से ध्यान में रखा गया है और सजा के प्रश्न पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें न्यायालय ने अपराध के समय अभियुक्तों की परेशान या असंतुलित मनःस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मृत्युदंड न देना उचित समझा शमशुल कंवर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1995) 4 एससीसी 430, लहना बनाम हरियाणा राज्य, (2002) 3 एससीसी 76 और

ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, (1999) 3 एससीसी 19. फ्रांसिस बनाम केरल राज्य, ख्1975, 3 एससीसी 825 में, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गईं।

फिर भी, यह तय करने में कि क्या मामला हत्या के लिए निर्धारित दो दंडों में से कम गंभीर दंड का हकदार है, संबंधित पक्षों के बीच संबंधों का इतिहास, पृष्ठभूमि, संदर्भ, या अपराध की तथ्यात्मक सेटिंग, और उद्देश्यों की ताकत और प्रकृति अपराधी के दिमाग पर काम करना, प्रासंगिक विचार हैं। इनके द्वारा उत्पन्न भावनाओं और दिमाग की स्थिति, हालांकि एक अपवाद लाने के लिए अपर्याप्त है, कम गंभीर सजा देने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है।

दो अन्य पुलिसकर्मियों की बिना किसी पूर्वचिन्तन और बिना किसी उद्देश्य के हत्या से यह भी पता चलता है कि ये कृत्य घबराहट की प्रतिक्रिया और उन्माद की स्थिति में किए गए थे। यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह निश्चितता के साथ कहा जा सके कि जानलेवा हमले संकल्पना में शैतानी और निष्पादन में क्रूर थे जैसा कि बचन सिंह के मामले (सुप्रा) में बताया गया है। न ही यह कहा जा सकता है कि 'अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थितियों से पता चलता है कि अपराधी समाज के लिए खतरा है या यदि तत्काल मामले में मौत की सजा नहीं दी गई तो समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा को झटका लगेगा। सबसे ऊपर, मौत की सजा है काफी समय से चिम को परेशान कर रहा था।

अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि मामले के तथ्य रणधीर बसु बनाम बंगाल राज्य, (2000) 3 एससीसी 161 और अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार

राज्य, (1989) 3 एससीसी 5 के तथ्यों के काफी करीब हैं। जिसमें न्यायालय ने कई हत्या के मामलों में मौत की सज़ा देने का विकल्प नहीं चुना। अनुशासित बल के एक सदस्य द्वारा साथी-पुलिसकर्मियों की अंधाधुंध हत्या निस्संदेह एक गंभीर कारक है, लेकिन ऊपर चर्चा की गई अन्य कम करने वाली परिस्थितियों से इसकी भरपाई होती है और इसलिए, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि मौत की सजा उचित सजा नहीं है। इसलिए, हमने अपील के तहत फैसले को रद्द कर दिया है क्योंकि इसने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए मौत की सजा की पुष्टि की है।

अपीलकर्ता को आजीवन कारावास और 1,000 रुपये रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। 1,000 रुपये और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की कैद भुगतनी होगी।

हालाँकि, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए दूसरे आरोप का गंभीर मामला यह है कि उसने तीन व्यक्तियों की हत्या के गैरकानूनी उद्देश्य के लिए स्टेन-गन और एसएलआर का इस्तेमाल किया। इस आशय का कोई सबूत नहीं है कि इस्तेमाल किया गया हथियार, अर्थात् स्टेन-गन, शस्त्र अधिनियम की धारा 2 (1) (आई) के अर्थ के भीतर 'निषिद्ध हथियारों के विवरण का उत्तर देता है। सार्जेंट मेजर की रिपोर्ट जिसे हथियार केवल इस आशय के लिए भेजे गए थे कि वे काम करने की

स्थिति में थे। धारा 27 के तहत अपराध के संबंध में ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई थी। हालाँकि, धारा 2 (1) (आई) के अर्थ के अंतर्गत, सभी संभावनाओं में, यह हो सकता है कि अपीलकर्ता को धारा 27 (3) के तहत दोषी ठहराना उचित नहीं है जिसमें मौत की चरम सजा का प्रावधान है। इसलिए शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है।

परिणामस्वरूप, ऊपर निर्धारित सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्पीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार वर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |